

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 53/18

गनी पुत्र वजीरा जाति गददी निवासी दोनायचा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांतान

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर

2. राजस्थान राज्य जरिये अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु०न० 3/18 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूंगर मु०न० 452/16 निर्णय दिनांक 30.1.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांतान की ओर से श्री कमलेश गुर्जर
2. रेस्पोटेडान की ओर से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 17.10.2019

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु०न० 3/18 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के प्रकरण संख्या 452/16 दिनांक 30.1.17 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में अपीलांत द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के निर्णय दिनांक 30.1.17 के विरुद्ध प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि अपीलार्थी को ग्राम दोनायचा के आराजी ख०न० 1220 रकबा 0.06 है० एवं ख०न० 1251 रकबा 0.34 है० चारागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से गेहूँ व सरसो की फसल की काश्त करने का कर्ता मानकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरुद्ध शारित आरोपित कर मौके से बंदखल करने के अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ पेश की गई थी। अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांत की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोटेडान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि निर्णय दोनों अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को ग्राम दोनायचा की आराजी ख0न0 1220 व 1251 कुल रकबा 0.40 है0 चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए निर्णय पारित किया है जबकि इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित किया है। जो की पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट है। अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने संबंधी कोई रिकार्ड नहीं होने पर भी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर जो निर्णय पारित किया है। वह निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोंडने का शपथ पत्र भी अपील के साथ पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त फरमाया जावे।


रेस्पोंड के विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील में बताया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामिल अपीलार्थी द्वारा स्वयं प्राप्त की जाकर की गई है। तथा अपीलार्थी स्वयं अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूंगर के यहाँ उपस्थित भी हुआ है। अपीलार्थी सरकारी भूमि पर अतिचार करने की शपथ पत्रावली होने के कारण ही उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर ही अधिनस्थ न्यायालय अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म चारागाह भूमि है। जो बेजुवान जानवरों के चरने के काम आती है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियों की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा तथा बेजुवान जानवरों के साथ अन्याय होगा। अतः अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। निर्णय विधि अनुरूप किये गये हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षों की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा ग्राम दोनायचा की आराजी ख0न0 1220 व 1251 कुल रकबा 0.40 है0 चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाने के फलस्वरूप ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर अतिचार नही होने के संबंध मे साक्ष्य सबूत पेश करने की अपेक्षा की गई थी। अपीलार्थी द्वारा स्वयं नोटिस की प्रति प्राप्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ परन्तु उसके द्वारा अतिचार नही होने बाबत किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया। अपीलार्थी द्वारा आराजी ख0न0 1220 पर गेहूँ एवं ख0न0 1251 पर सरसो की फसल काश्त करके अतिचार किया गया है एवं बार बार अतिचार करने के उपरान्त ही पटवारी हल्का द्वारा पश्चातवर्ती अतिचारी होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा कब्जा की गई भूमि का रकबा काफी बडा है एवं किस्म भी चारागाह है जो बेजूबान जानवरो के चरने के काम मे आती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किये गये है वह विधि अनुरूप है। उनमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 3/18 निर्णय दिनांक 9.2.18 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूंगर मु0न0 452/16 निर्णय दिनांक 30.1.17 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


(बी0एल0 सहायिका)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

